



भारत में सहकारिता और उसका विकास

प्रलम्ब के लिये:

[सहकारी कषेत्र, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002, 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011, बहुराज्य सहकारी सोसायटी \(संशोधन\) अधिनियम, 2022, IFFCO](#)

मेन्स के लिये:

भारत में सहकारी समितियों की स्थिति, भारत में सहकारी समितियों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने गुजरात में 102वें अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस (International Day of Cooperatives) के अवसर पर आयोजित 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम को संबोधित किया।

नोट:

- अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है।
 - वर्ष 2024 की थीम "कोऑपरेटिव बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर फोर ऑल" है।
 - यह थीम संयुक्त राष्ट्र के आगामी समिटि ऑफ द फ्यूचर के उद्देश्यों के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है जिसकी थीम "मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फोर ए बेटर दुमॉरो" है।
 - सामाजिक विकास में सहकारिता पर वर्ष 2023 की संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट के अनुसार सहकारिता हमेशा से हाशियाई समूहों सहित सभी व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य करती रही है।
 - यह दिवस वर्ष 2025 के अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा।

भारत में सहकारी समितियों का विकास किस प्रकार हुआ?

- परिचय:
 - सहकारी समितियाँ जन-केंद्रित उद्यम हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा उनकी साझा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिये किया जाता है।
 - कृषि, ऋण, डेयरी, आवास और मत्स्य पालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 800,000 से अधिक सहकारी समितियों के साथ भारत का सहकारिता नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है।
 - कृषि ऋण के वितरण में 20%, फर्टिलाइज़र्स के वितरण में 35%, चीनी उत्पादन में 31%, गेहूँ की खरीदी में 13% और धान की खरीदी में 20% का योगदान सहकारिता क्षेत्र दे रहा है।

7 Cooperative Principles



■ स्वतंत्रता पूर्व युग में सहकारी समितियाँ:

- भारत में पहला सहकारी अधिनियम: भारतीय अकाल आयोग (1901) द्वारा वर्ष 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित हुआ, जिसके बाद (संशोधित) सहकारी समिति अधिनियम, 1912 पारित हुआ।
- मैकलेगन समिति: वर्ष 1915 में सर एडवर्ड मैकलेगन की अध्यक्षता में एक समिति को इस विषय का अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिये नियुक्त किया गया था कि क्या सहकारी आंदोलन आर्थिक तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ दशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं।
- मॉटेग्यू-चेमसफोर्ड सुधार: 1919 के मॉटेग्यू-चेमसफोर्ड सुधारों के माध्यम से सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गया जिसने इस आंदोलन को और गति प्रदान की।
- आर्थिक मंदी के बाद, 1929: सहकारी समितियों के पुनर्गठन की संभावनाओं की जाँच करने के लिये मद्रास, बॉम्बे, त्रावणकोर, मैसूर, गुवालयिर और पंजाब में विभिन्न समितियों की नियुक्ति की गई।
- गांधीवादी समाजवादी दर्शन: गांधीजी के अनुसार, समाजवादी समाज के निर्माण और सत्ता के पूर्ण वकेंद्रीकरण के लिये सहयोग आवश्यक था।
 - उनके अनुसार लोगों को सशक्त बनाने के लिये सहयोग एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।
 - महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 'फीनक्स सेटलमेंट' की स्थापना एक समाजवादी पद्धति में सहकारी संस्था के रूप में की थी।
 - उन्होंने इस अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित परिवारों के लिये पुनर्वास सहकारी बस्ती के रूप में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की।

■ स्वतंत्रता के बाद के भारत में सहकारिता:

- प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56): व्यापक सामुदायिक विकास के लिये सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया।
- बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002: बहु-राज्य सहकारी समितियों के गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली हेतु प्रावधान करता है।
 - बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2022 ने बहु-राज्य सहकारी समितियों में बोर्ड चुनावों की देख-रेख के लिये सहकारी चुनाव प्राधिकरण की शुरुआत की।
- 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2011: सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया (अनुच्छेद 19)।
 - सहकारी समितियों पर राज्य की नीतिका एक नया नदिशक सदिधांत प्रस्तुत किया गया (अनुच्छेद 43-B)।
 - संविधान में "सहकारी समितियाँ" शीर्षक से एक नया भाग IX-B जोड़ा गया (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT)।
 - बहु-राज्य सहकारी समितियों (multi-state cooperative societies- MSCS) को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिये संसद को अधिकार दिया गया और साथ ही अन्य सहकारी समितियों के लिये राज्य विधानसभाओं को अधिकार सौंपा गया।
- केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना (2021): सहकारी मामलों की ज़िम्मेदारी संभाली गई, जिसकी देख-रेख पहले कृषि मंत्रालय करता था।

■ सहकारिता का प्रभाव:

- हाशिये पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाना: गुजरात में अमूल डेयरी सहकारी संस्था, जिसके 3.6 मिलियन से अधिक दुग्ध उत्पादक हैं (जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों से हैं), दुग्ध के लिये उचित मूल्य उपलब्ध कराकर तथा विशेष रूप से महिलाओं हेतु आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाती है।
- कृषि उत्पादकता और विपणन को बढ़ावा देना: भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (Indian Farmers Fertiliser

Cooperative Limited- IFFCO) विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक है। IFFCO जैसी सहकारी संस्थाएँ कसिनो को उर्वरक, बीज और ऋण जैसे आवश्यक कृषि इनपुट प्रतस्पर्द्धी कीमतों पर उपलब्ध कराती हैं, जिससे उत्पादकता तथा कृषि आय में वृद्धि होती है।

- **आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाना:** केरल राज्य दुग्ध वपिणन संघ (मलिमा), एक डेयरी सहकारी संस्था है, जो कसिनो से दुग्ध खरीदती है और इसे केरल में उपभोक्ताओं को कफायती दामों पर उपलब्ध कराती है। इससे उत्पादकों के लयिबाजार तक पहुँच सुनिश्चित होती है तथा लोगों को आवश्यक डेयरी उत्पाद उपलब्ध होते हैं।
- **समावेशी विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना:** नीतिआयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि महाराष्ट्र में चीनी सहकारी समितियों 5 लाख से अधिक लोगों (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष) को रोजगार प्रदान करती हैं, जो ग्रामीण रोजगार सृजन एवं आय सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

सहकारिता को मज़बूत करने के लयि सरकारी पहल

- **UCB के लयि अम्बरेला संगठन:** RBI ने UCB क्षेत्र के लयि एक अम्बरेला संगठन (Umbrella Organization- UO) के गठन हेतु नेशनल फेडरेशन ऑफ अरबन को-ऑपरेटिव बैंकस एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (National Federation of Urban Co-operative Banks and Credit Societies Ltd.- NAFCUB) को मंजूरी दे दी है, जो लगभग 1,500 UCB को आवश्यक IT बुनियादी ढाँचा और परिचालन सहायता प्रदान करेगा।
- **पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करना:**
 - **PACS के लयि आदर्श उपनयिम,** जिससे वे बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी संस्थाएँ बन सकें।
 - **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी वकिंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना (2023)।**
 - सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि **वर्ष 2029 तक प्रत्येक पंचायत में एक PACS हो,** जिससे प्रधानमंत्री मोदी के 'सहकार से समृद्धि' (सहयोग से समृद्धि) के दृष्टिकोण को पूरा किया जा सके।
- **अन्य पहल:**
 - प्रामाणिक एवं अद्यतन डेटा संग्रह हेतु राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस।
 - सहकारी कल्याण के लयि **राष्ट्रीय सहकारी विकास नगिम (National Cooperative Development Corporation- NCDC)** द्वारा 2000 करोड़ रुपए के बांड जारी किये गए।
 - सहकारी समितियों को GeM पोर्टल पर 'खरीदार' के रूप में शामिल करना।
 - NCDC का वसितार कर इसकी सीमा और गहराई बढ़ाई जाएगी।
 - **राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (National Cooperative Organic Limited- NCOL)** की स्थापना जैविक खेती को बढ़ावा देने और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लयि की गई थी।
 - **भारत ऑर्गेनिक आटा** का शुभारंभ।

सहकारी समितियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- **शासन संबंधी चुनौतियाँ:** सहकारी समितियाँ पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक नरिणय लेने की प्रक्रियाओं की कमी की चुनौतियों से जूझती हैं।
 - सदस्यों की सीमति भागीदारी, हाशयि पर पड़े समुदायों का अपर्याप्त प्रतनिधित्व तथा कुछ व्यक्तियों के पास सत्ता का संकेंद्रण सहकारी उद्यमों की समावेशी प्रकृति को कमजोर कर सकता है।
- **वत्तीय संसाधनों तक सीमति पहुँच:** कई सहकारी समितियाँ, खास तौर पर हाशयि पर पड़े समुदायों की सेवा करने वाली, वत्तीय संसाधनों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करती हैं। उनके पास अक्सर पारंपरिक वत्तीय संस्थानों द्वारा अपेक्षित संपारश्वकि या औपचारिक दस्तावेजों की कमी होती है, जिससे ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
- **सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ और बहषिकार:** सहकारी समितियों को अक्सर समावेशिता की कमी, संरचनात्मक असमानताओं आदिसे संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ:** बुनियादी ढाँचे की कमी और कनेक्टिविटी की कमी उनकी दक्षता तथा प्रभावशीलता को प्रभावित करती है, जिससे पहुँच सीमति हो जाती है।
- **तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं का अभाव:** प्रशिक्षण और कौशल विकास पहलों का अभाव एक तथा चुनौती है, जिसके कारण मानव संसाधन पुराने हो जाते हैं।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक कारक:** संभावित सदस्यों के बीच सहकारी मॉडल और इसके लाभों के बारे में जागरूकता की कमी उनकी भागीदारी को सीमति करती है।
 - कुछ मामलों में, सामाजिक पदानुक्रम और जाति-आधारित विभाजन सहकारी समितियों के भीतर न्यायसंगत भागीदारी तथा प्रतनिधित्व के लयि बाधाएँ पैदा करते हैं।

आगे की राह

- वत्तीय रिपोर्टिंग के लयि डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू करें, नयिमति ऑडिट करें और नरिणय लेने की प्रक्रियाओं में सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें।
- हाशयि पर पड़े समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लयि लचीली संपारश्वकि आवश्यकताओं के साथ सहकारी विकास नधि स्थापित करें। सहकारी

- समितियों को **क्राउडफंडिंग**, **सामाजिक प्रभाव बॉण्ड** और अन्य अभिनव वित्तपोषण समाधानों का पता लगाने के लिये प्रोत्साहित करें।
- **हाशिये पर पड़े समुदायों के सदस्यों को शक्ति करने** और आकर्षित करने के लिये आउटरीच कार्यक्रम तैयार करें, जसमें वशिष्ट आवश्यकताओं तथा चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
 - ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के विकास में सरकारी नविश की वकालत करें, सहकारी समितियों के लिये कनेक्टविटी और बाजारों तक पहुँच में सुधार करें।
 - सहकारी सदस्यों और प्रबंधकों के लिये कौशल निर्माण कार्यशालाओं की पेशकश करने के लिये सरकारी एजेंसियों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी करें।
 - संभावित सदस्यों को सहकारी समितियों के लाभों और सदिधांतों के बारे में शक्ति करने के लिये **स्थानीय भाषाओं में लक्षित जागरूकता अभियान** शुरू करें।

दृष्टि मनेस प्रश्न:

प्रश्न. भारत में सहकारी क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। भारत में सहकारी आंदोलन को मज़बूत करने के लिये इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कसि की कृषितथा सहबद्ध गतविधियों में ऋण के वतिरण में सबसे अधिक हसिसेदारी है? (2011)

- वाणजियकि बैंकों की
- सहकारी बैंकों की
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की
- सूक्ष्म-वत्तित (माइक्रोफाइनेंस) संस्थाओं की

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत के संदर्भ में, नमिनलखिति पर वचिार कीजिये: (2010)

- बैंकों का राष्ट्रियकरण
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन
- बैंक शाखाओं द्वारा गाँवों को अपनाना

उपर्युक्त में से कसि/कनि को, भारत में "वत्तित्तीय समावेशन" प्राप्त करने के लिये उठाए गए कदम/कदमों के रूप में माना जा सकता है?

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. "भारतीय शासकीय तंत्र में, गैर-राजकीय कर्त्ताओं की भूमिका सीमति ही रही है।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2016)

प्रश्न . "गाँवों में सहकारी समितिको छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।" - अखलि भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषिवत्तित की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। कृषिवत्तित प्रदान करने वाली वत्तित संस्थाओं को कनि बाधाओं और कसौटियों का सामना करना पडता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का कसि प्रकार उपयोग किया जा सकता है? (2014)

